अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा योजनाओं पर टिप्पणियां - संशोधित अनुमान 2004-2005 तथा बजट अनुमान 2005-2006 वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 32 आर्थिक कार्य विभाग

तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि

राष्ट्रमंडलीय तकनीकी सहयोग निधि (सी. एफ. टी. सी.) की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई है । सी. एफ. टी. सी. के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों में सामान्य तकनीकी सहायता कार्यक्रम, निर्यात बाजार विकास कार्यक्रम, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आते हैं। सदस्य देशों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें विशेषज्ञों, सलाहकारों तथा परामर्श दाताओं की सेवाएं और अध्ययन वृत्तियां/छात्रवृत्तियां इत्यादि उपलब्ध करायी जाती हैं।

भारत 1971-72 से सी. एफ. टी. सी. को अपना अंशदान देता आ रहा है । 2005-2006 के लिए भारत का अंशदान मोटे तौर पर 6.20 करोड़ रुपए है।

निधि में भारत की ओर से अंशदान के रुपया-भाग का प्रयोग भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रशिक्षण को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ-साथ इसका प्रयोग सी. एफ. टी. सी. संबंधी कार्यों के लिए भर्ती किए गए भारतीय राष्ट्रिकों के वेतन तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा संबंधी स्वर्चों को पूरा करने और सी. एफ. टी. सी. के मामलों के संबंध में भारत का दौरा करने वाले सी.एफ.टी.सी. कार्मिकों के स्थानीय स्वर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कोलम्बो योजना

भारत कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को भारत में उनके नामित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं तथा विशेषज्ञों की सेवाओं और सहायक उपस्करों के रूप में तकनीकी और अन्य सहायता उपलब्ध करा रहा है। वित्तीय आवंटन इस प्रकार हैं:-

(हजार रुपए)

| ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 40000 | 40000 | 40000 |

कोलम्बो आयोजना ब्यूरो (आयोजना परिषद का सचिवालय) और कोलम्बो आयोजना स्टाफ कालेज के लिए भी भारत के अंशदान की व्यवस्था है। इस राशि के एक छोटे अंश का उपयोग कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज को पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। वित्तीय आवंटन इस प्रकार है:-

(हजार रुपए)

| ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 5000 | 4600 | 5000 |

NOTES ON DEMANDS FOR GRANTS AND NOTES ON IMPORTANT PROJECTS AND SCHEMES - REVISED ESTIMATES 2004-2005 AND BUDGET ESTIMATES 2005-2006 MINISTRY OF FINANCE

DEMAND NO.32 DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

COMMONWEALTH FUND FOR TECHNICAL COOPERATION (C.F.T.C.)

The Commonwealth Fund for Technical Co-operation (CFTC) has been set up to provide technical assistance to the member countries of the Commonwealth in various fields. The activities of the CFTC cover general technical assistance programmes, exports market development programme, education and training programme. Services of the experts, advisers and consultants and fellowship/scholarships are made available to member countries on requests.

India has been contributing to the CFTC since 1971-72. India's contribution for 2005-2006 is roughly Rs.6.20 crore.

The Rupee portion of India's contribution to the Fund is used for financing the training of foreign nationals in India and meeting the salaries and international travel costs of Indian nationals recruited for CFTC assignments and local cost of CFTC personnel visiting India in connection with CFTC matters.

COLOMBO PLAN

India is providing technical and other assistance to the members of the Colombo Plan countries in the form of training facilities to their nominees in India and services of Experts and supply of ancillary equipments. Financial allocations are as under:-

(Rupees in thousands)

| B.E.2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|---------------|----------------|----------------|
| 40000 | 40000 | 40000 |

Provision is also made for India's contribution to the Colombo Plan Bureau (Sectt. of the Plan Council) and the Colombo Plan Staff College. A small portion of this account is also utilised for supply of books and periodicals to the Colombo Plan Staff college. Financial allocations are as under:-

(Rupees in thousands)

| B.E.2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|---------------|----------------|----------------|
| 5000 | 4600 | 5000 |

नवंबर 1984 के दंगों से प्रभावित कर्जदारों को राहत

भारत सरकार ने अप्रैल, 1990 में यह निर्णय लिया था कि नवंबर 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को और उन व्यक्तियों को जिन्होंने ''नवम्बर,1984 के दंगों से प्रभावित कर्ज़दारों के लिए केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता योजना'' के अनुसार बैंकों से कर्ज लिया हुआ था, राहत दी जाए । इस योजना को अब 25,000 रुपए की सीमा तक के अल्प ऋणों की पूर्ण माफी के लिए संशोधित किया गया है। वर्ष 2005-2006 के लिए 1.16 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

विश्व पर्यावरण सुविधा तथा विश्व न्यास निधि

विश्व पर्यावरण सुविधा एक प्रायोगिक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण के संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने में मदद के लिए अनुदान अथवा रियायती ऋण दिए जाएंगे । कार्यक्रम का विकास विश्व बैंक (आई. बी. आर. डी), यू. एन. डी. पी. तथा यू. एन. ई. पी. द्वारा किया गया है । इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व पर्यावरण न्यास निधि नामक एक निधि एक बिलियन अमरीकी डालर की केन्द्रीय निधि से स्थापित की गई है । कार्यक्रम के एक सदस्य के रूप में भारत 4 मिलियन एस. डी. आर. का अंशदान देने के लिए सहमत हो गया है जो मोटे तौर पर 10.6 करोड़ रुपए के बराबर है। बजट अनुमान 2005-2006 के अन्तर्गत, 10.66 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है ।

मांग संख्या 33 करेंसी और सिक्का निर्माण प्रभाग (आर्थिक कार्य विभाग)

1. भारत सरकार की टकसालें

मुम्बई, कोलकत्ता, हैदराबाद (चेर्लापल्ली) और नोएडा में चार टकसालें है । इन टकसालों का मुख्य कार्य सिक्कों की घरेलु मांग को पूरी करने के लिए सिक्कों की ढलाई करना है ।

ये टकसालें संचलन से हटाए गए सिछों की जांच तथा उनका निपटान भी करती हैं तथा नकली और संदिग्ध सिछों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ राय देती हैं । ये विभिन्न सरकारी विभागों तथा विश्वविद्यालयों जैसी अन्य संस्थाओं के लिए पदकों का निर्माण भी करती हैं । मुंबई और कलकत्ता टकसालों से संबद्ध परस्र विभाग सिछों, पदकों, बैजों आदि के लिए सोने, चांदी और मिश्र धातुओं की परस्र करते हैं। मुंबई टकसाल में स्मारक सिछों तथा बाट, आयतन एवं लंबाई से संबंधित परिमापों का विनिर्माण किया जाता है । इसमें सोना गलाने, शोधन करने और ढालने का काम भी होता है। मुंबई और कोलकाता टकसाल द्वारा संचालित एकत्रीकरण एवं सुपुर्दगी केन्द्रों के माध्यम से ये अशोधित सोने के बदले स्टैन्डर्ड सोने की छड़ों के विनिमय का काम भी करती हैं। कोलकाता टकसाल स्मारक सिछ्ठे एवं मैडल भी बनाती है।

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान चार टकसालों में सिक्कों के उत्पादन की उपलब्धियां निम्न प्रकार है:

उत्पादन का टकसालवार ब्यौरा

(दस लाख अदद)

| इकाई नाम | 2003-04 | 2004-2005(31.12.2004 तक) |
|---------------------------------|----------|--------------------------|
| आई.जी.एम. मुम्बई | 869.0859 | 224.6272 |
| आई.जी.एम. कोलकत्ता | 767.9025 | 224.6025 |
| आई.जी.एम. चेरलापल्ली (हैदराबाद) | 680.9975 | 282.0510 |
| आई.जी.एम. नौएडा | 840.1300 | 239.9050 |

RELIEF TO NOVEMBER'84 RIOTS AFFECTED BORROWERS

Government of India decided in April, 1990 to extend relief in deserving cases to the persons affected by November 1984 Riots and who had taken loans from banks as per the "Central Interest Subsidy Scheme for November' 84 Riots Affected Borrowers" of September, 1990. The Scheme has since been modified for providing complete waiver of small loans upto a limit of Rs. 25000. Rs.1.16 crore has been provided for 2005-2006.

THE GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY AND THE GLOBAL TRUST FUND

The Global Environment Facility (GEF) is a pilot programme under which grants or concessional loans will be provided to Developing Countries to help them implement programmes that protect the global environment. The Programme has been developed by World Bank (IBRD), UNDP and UNEP. To fund this programme, a fund named the Global Environment Trust Fund (GETF) has been set up with a core fund of US \$ one billion. India, as a member of the programme, has agreed to contribute SDR 4 million, roughly equivalent to Rs.10.6 crore. Under BE 2005-2006, Rs.10.66 crore has been provided.

DEMAND NO.33 CURRENCY AND COINAGE DIVISION (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

1. INDIA GOVERNMENT MINTS

There are four Mints at Mumbai, Kolkata, Hyderabad (Cherlapally) and Noida. The main function of the Mints is minting of coins to meet domestic requirement.

The Mints also examine and dispose of withdrawn coins and tender expert opinion on counterfeit and doubtful coins. They also manufacture medals for various Government departments and other institutions like Universities. The Assay Departments attached to Mumbai and Kolkata Mint Assay Gold, Silver and alloys for coins, medals, badges etc. The Mumbai Mint manufactures commemorative coins and weights, volume and length measures. It also undertakes Gold melting, refining and casting work. They also do the work of exchanging standard Gold Bars against un-refined gold through collection-cum-delivery centres operated by Mumbai and Kolkata Mints. Kolkata Mint also makes commemorative coins and medals.

The production achievements of coins at four Mints during the year 2003-2004 and 2004-2005 are as under:-

MINT-WISE BREAK UP OF PRODUCTION

(In Million Pcs.)

| | | (In Million I Cs.) |
|------------------------------|----------|-----------------------------|
| Unit Name | 2003-04 | 2004-2005 (Upto 31.12.2004) |
| IGM, Mumbai | 869.0859 | 224.6272 |
| IGM, Kolkata | 767.9025 | 224.6025 |
| IGM, Cherlapally (Hyderabad) | 680.9975 | 282.0510 |
| IGM, Noida | 840.1300 | 239.9050 |

2. भारत प्रतिभृति मुद्रणालय, नासिक रोड

भारत प्रतिभृति मुद्रणालय का मुख्य कार्य डाक टिकट, डाक और डाक-भिन्न लेखन सामग्री, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टैट बैंक के चैक, बांड, बचत-पत्र, पोस्टल आर्डर, पासपोर्ट, वचन-पत्र तथा ऐसे अन्य प्रतिभति दस्तावेजों का मद्रण करना है जिनकी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों को आवश्यकता हो सकती है । इस मुद्रणालय ने एम. आई. सी. आर. चैकों आदि का मुद्रण भी शुरू कर दिया है। मुद्रणालय से सम्बद्ध केन्द्रीय स्टाम्प डिपो निर्मित सामग्री की आपूर्ति का कार्य करता है।

मद्रणालय में 2003-04 और 2005-2005 के दौरान उत्पादन उपलब्धियां इस प्रकार है:-

| | | | (करोड़ अदद) |
|----------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| | | निम्न के संबंध | में वार्षिक उत्पादन |
| क्रम सं. | मद | 2002-03 | 2003-04 |
| 1. | पोस्ट कार्ड | 3.2353 | 0.177 |
| 2. | साधारण लिफाफे | 1.6383 | 0.8774 |
| 3. | रजिस्ट्री लिफाफे | 0.9893 | 0.5560 |
| 4. | अन्तर्देशीय पत्र | 2.9838 | 1.9386 |
| 5. | ऐयरोग्राम | 0.4163 | 0.2757 |
| 6. | सरकारी डाक टिकटें | 3.1739 | 1.4453 |
| 7. | विशिष्ट डाक वाणिज्यिक टिकटें | 19 नग | 31 नग |
| 8. | डाक-भिन्न चिपकनेवाली टिकटें | 1.9775 | 1.1184 |
| 9. | गैर-न्यायिक और सम्बद्ध स्टाम्प | 17.6569 | 8.7010 |
| 10. | एनएससी/केवीपी बचत लिखतें | 12.9006 | 7.4792 |
| 11. | एमआईसीआर-भिन्न चैक | 0.3107 | 0.2923 |
| 12. | एम.आई.सी.आर.चैक | 4.6325 | 4.3260 |
| 13. | विविध प्रतिभूति प्रपत्र | 2.2730 | 1.3748 |
| 14. | पासपोर्ट और संबद्ध पुस्तिकाएं | 0.3678 | 0.2588 |
| 15. | स्टिकर/लेबल/कार्ड/सील | 0.9250 | 0.2740 |

3. प्रतिभृति मुद्रणालय, हैदराबाद

प्रतिभृति मद्रणालय विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की डाक-लेखन सामग्री और मैच उत्पाद-शुल्क बैंड रोलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत प्रतिभृति मुद्रणालय, नासिक के उत्पादन की अनुपूर्ति करता है। यह समुचे देश में मांगकर्ताओं की अन्तर्देशीय पत्रों तथा मैच उत्पाद-शुल्क बैंड-रोलों की मांग की आपूर्ति भी करता है । मद्रणालय दक्षिणी राज्यों के लिए निम्न मुख्य वर्ग के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का मद्रण करता है ।

वर्ष 2003-04 और 2004-2005 के दौरान इस मुद्रणालय में उत्पादन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

2. INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD

The main functions of India Security Press is to print Postal and non-postal stationary, judicial and non-judicial stamps, RBI/SBI Cheques, Bonds, Saving Certificates, Postal Orders, Passports, Promissory Notes and such other Security documents as may be required by the Central and State Governments, Public Sector Undertakings and Local Bodies. It has also started printing MICR Cheques etc. The Central Stamps Depot attached to the Press deals with the supply of finished products.

Production achievements of the Press during 2003-04 and 2004-2005 are as under:-

(in crores of Pcs.)

| | | Annual Production for | |
|---------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | |
| Sl. No. | Items | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | Post Cards | 3.2353 | 0.177 |
| 2. | Ordinary Envelope | 1.6383 | 0.8774 |
| 3. | Registration Envelope | 0.9893 | 0.5560 |
| 4. | Inland Letter Cards | 2.9838 | 1.9386 |
| 5. | Aerogramme | 0.4163 | 0.2757 |
| 6. | Public Postage Stamps | 3.1739 | 1.4453 |
| 7. | Special Postage Comm. Stamps | 19 issues | 31 issues |
| 8. | Non Postal Adhesive Stamps | 1.9775 | 1.1184 |
| 9. | Non-Judicial & Allied Stamps | 17.6569 | 8.7010 |
| 10. | NSC/KVP (Saving Instruments) | 12.9006 | 7.4792 |
| 11. | Non-MICR Cheques | 0.3107 | 0.2923 |
| 12. | MICR Cheques | 4.6325 | 4.3260 |
| 13. | Misc. Security Forms | 2.2730 | 1.3748 |
| 14. | Passport & Allied Booklets | 0.3678 | 0.2588 |
| 15. | Sticker/Label/Cards/Seals | 0.9250 | 0.2740 |

3. SECURITY PRINTING PRESS, HYDERABAD

Security Printing Press supplements the output of India Security Press, Nasik mainly to cater to the needs of Southern States in respect of postal stationery and match excise banderols. It has also been supplying Inland Letter Cards and match excise banderols to indentors all over the country. The press is printing non-judicial stamp papers of lower denominations for Southern States.

Production achievements of the Press during 2003-04 and 2004-2005 are as under:-

| | | (करोड़ अदद) |
|--------------------------------|---------|---------------------------|
| मद | 2002-03 | 1.4.2004 से 31.12.2004 तक |
| | उत्पादन | उत्पादन |
| पोस्ट कार्ड | 16.66 | 18.97 |
| अन्तर्देशीय पत्र कार्ड | 10.35 | 5.46 |
| लिफाफे | 05.56 | 0.60 |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प | | |
| गैर-न्यायिक स्टाम्प | 09.42 | 2.09 |
| सैन्य पत्र आई ए एफ 5 | 02.23 | 1.89 |
| सैन्य पत्र आई ए एफ 6 | 02.54 | 1.35 |
| हरे लिफाफे | | |
| किसान विकास पत्र | 01.90 | 0.30 |
| इंडियन पोस्टल आर्डर्स | | 3.16 |

4. करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड

करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड, 5 रुपए,10 रुपए, 50 रुपए 100 रुपए, 500 रुपए एवं 1000 रुपये के नोट छापता है ।

वर्ष 2003 और 2004 के दौरान नोट अदद के उत्पादन/निर्गम आंकड़े निम्नानुसार है:-

| जोड़ | 2,594,167,000 | 2,610,000,000 | 2,693,289,000 | 2,637,800,000 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| हजार रुपए | 23,483,000 | 20,000,000 | 77,440,000 | 82,300,000 |
| पांच सौ रुपए | 181,064,000 | 192,000,000 | 37,339,000 | 29,500,000 |
| सौ रुपए | 556,430,000 | 499,000,000 | 677,650,000 | 752,000,000 |
| पचास रुपए | 200,000,000 | 192,000,000 | 360,000,000 | 368,000,000 |
| दस रुपए | 759,340,000 | 779,000,000 | 1,329,420,000 | 1,168,000,000 |
| पांच रुपए | 873,850,000 | 928,000,000 | 211,440,000 | 238,000,000 |
| | दौरान उत्पादन | दौरान निर्गत | दौरान उत्पादन | दौरान निर्गत |
| मूल्य वर्ग | वर्ष 2003 के | वर्ष 2003 के | वर्ष 2004 के | वर्ष 2004 के |

5. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोट छापता है । यह मुद्रणालय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा साथ ही करेंसी नोट मुद्रणालय, भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय और प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रयोग के लिए भी स्याही बना रहा है ।

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान मुद्रणालय में उत्पादन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

| मूल्य वर्ग | मांग पत्र | उत्पादन और | संतुष्टि |
|------------|------------|------------|----------|
| | मिलियन में | प्रेषण | स्तर |
| 20 रुपए | 400 | 371 | 93% |
| 50 रुपए | 850 | 610 | 72% |
| 100 रुपए | 600 | 509 | 85% |
| 500 रुपए | 75 | 30 | 40% |

(in crores of Pcs.)

| | | (in crores of 1 cs.) |
|-------------------------|------------|------------------------|
| Item | 2003-04 | 1.4.2004 to 31.12.2004 |
| | Production | Production |
| Post Cards | 16.66 | 18.97 |
| Inland Letter Cards | 10.35 | 5.46 |
| Eenvelope | 05.56 | 0.60 |
| Central Excise Stamps | | ••• |
| Non-judicial stamps | 09.42 | 2.09 |
| Forces letters I.A.F. 5 | 02.23 | 1.89 |
| Forces letters I.A.F. 6 | 02.54 | 1.35 |
| Green Envelopes | | ••• |
| Kisan Vikas Patras | 01.90 | 0.30 |
| Indian Postal Orders | ••• | 3.16 |

4. CURRENCY NOTE PRESS, NASIK ROAD

Currency Note Press, Nasik Road prints notes in denominations of Rs.5/-, Rs.10/-, Rs.50/-, Rs.100/-, Rs.500/-, and Rs.1000/-.

Production/output figures during the year 2003 & 2004 in Note pieces are shown below:

| Rs.500 | 181,064,000 | 192,000,000 | 37,339,000 | 29,500,000 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rs.1000 | 23,483,000 | 20,000,000 | 77,440,000 | 82,300,000 |
| Rs.50 | 200,000,000 | 192,000,000 | 360,000,000 | 368,000,000 |
| Rs.100 | 556,430,000 | 499,000,000 | 677,650,000 | 752,000,000 |
| Rs.5 | 873,850,000 | 928,000,000 | 211,440,000 | 238,000,000 |
| Rs.10 | 759,340,000 | 779,000,000 | 1,329,420,000 | 1,168,000,000 |
| Denomination | Output During the year 2003 | Issued During the year 2003 | Output During the year 2004 | Issued During the year 2004 |

5. BANK NOTE PRESS, DEWAS

Bank Note Press, Dewas, prints Bank Note of Rs.20/- Rs.50/- Rs.100/- Rs.500/- denominations. This press is also manufacturing ink for its own use as well as for the use of Currency Note Press, India Security Press and Security Printing Press.

Production achievements of the press during 2003-04 and 2004-2005 are as under :-

| Denominations | Indent in millions | Production and dispatches | Level of satisfaction |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dungas 20/ | 400 | 371 | 93% |
| Rupees 20/- | 400 | | |
| Rupees 50/- | 850 | 610 | 72% |
| Rupees 100/- | 600 | 509 | 85% |
| Rupees 500/- | 75 | 30 | 40% |

6. प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)

वर्ष 1967 में आरम्भ, प्रतिभूति कागज कारखाना बैंक नोट कागज तथा अन्य प्रतिभूति कागजों का निर्माण करता है एवं प्रतिभुति तथा मुद्रा/बैंक नोट मुद्रणालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारखाने की स्थापना से पूर्व, प्रतिभूति कागज तथा बैंक नोट कागज की संपूर्ण आवश्यकता को आयात से पूरा किया जाता था। वर्ष 2003-04 के दौरान वास्तविक तैयार उत्पादन 2563 मी. टन था। वर्ष 2004-05 के लिए लक्षित उत्पादन 2700 मी. टन पर निर्धारित किया गयाहै, जिसकी तुलना में दिनांक 31.12.2004 तक वास्तविक उपलब्धि 1730 मी. टन है। प्रतिभूति कागज कारखाने में 500 रुपए के मूल्य वर्ग का कागज पहली बार बनाया जा रहा है।

माांग संख्या 34 वित्तीय संस्थाओं को अदायगी

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना शीर्ष संस्था के रूप में उद्योग को सावधिक वित्त प्रदान करने हेतु 1964 में की गयी थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उद्योग के वित्त पोषण और संवर्धन में लगी अन्य सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की कार्य पद्धित में समन्वय करने और ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से संबंधित बजट प्रावधान का विवरण इस प्रकार है :-

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| (1) अनुदान (आयोजना-भिन्न) | 570.10 | 250.00 | 490.00 |

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई)

भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मध्यम और दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के तहत 1948 में की गई थी । इसकी पचास प्रतिशत शेयर पूंजी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा और शेष पचास प्रतिशत शेयर पूंजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा प्रतिष्ठानों आदि द्वारा धारित है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से संबंधित बजट प्रावधान नीचे दिये गये हैं :-

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 226.00 | 316.00 | 300.00 |

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

आई.सी.आई. बैंक रूपयों और विदेशी मुद्राओं में सावधिक ऋण देने की व्यवस्था करता है, शेयर को अभिदान करता है एवं हामीदारी भरता है और मुख्य रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं से प्राप्त किए गए ऋणों की वापसी अदायगी की गारण्टी भी देता है।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के बजट प्रावधान उपलब्ध विदेशी सहायता के एवज में प्रतिरूप निधियां देने व विदेशी मुद्रा जोखिम हेतू व्यवस्था करने से संबंधित हैं । इनका ब्यौरा निम्नलिस्वित है :-

6. SECURITY PAPER MILL, HOSHANGABAD (MADHYA PRADESH)

Commissioned in the year 1967, the Security Paper Mill manufactures Bank Note Paper and other Security Papers and caters to the requirement of Security and Currency/ Bank Note Printing Presses. Prior to establishment of the Mill, the entire requirement of Security Paper and Bank Note Paper were being met by import. The actual finished production achieved during the year 2003-04 was 2563 MTs. Target production for 2004-05 is fixed at 2700 MTs. against which the actual achievement till 31/12/2004 is 1730 MTs. The Rs.500/- denomination paper is being made first time at SPM.

DEMAND NO.34 PAYMENT TO FINANCIAL INSTITUTIONS

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA (IDBI)

The Industrial Development Bank of India (IDBI) was set up in 1964 as the apex institution for term finance for industry. IDBI is also vested with the responsibility of co-ordinating the working of other term lending institutions engaged in the financing and promotion of industry and assisting in the development of such institutions.

Budget Provisions relating to IDBI are given below:-

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) Grant (Non-Plan) | 570.10 | 250.00 | 490.00 |

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA (IFCI)

The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was established in 1948, under the Industrial Finance Corporation Act 1948 with the objective of providing medium and long term credits to Industrial concerns in India. Fifty per cent of its Share Capital is held by the Industrial Development Bank of India and the balance fifty per cent is held by Scheduled Commercial Banks, Cooperative Banks, Insurance concerns etc.

Budget provisions relating to IFCI are given below:-

(Rs. in crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 226.00 | 316.00 | 300.00 |

ICICI BANK

ICICI Bank provides term loans in rupees and foreign currencies, subscribes to and underwrites share and guarantees repayment of credit availed of from other institutions primarily for the purpose of capital assets.

Budget provisions relating to ICICI Bank are for passing on counterpart funds against available external assistance and for providing for foreign exchange risk. These are given below:-

| | | | (करोड़ रुपए) |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
| अनुदान | ••• | 50.00 | 37.50 |
| मुद्रा अंतर हेतु | | | |
| हेतु प्रतिरूप-भिन्न | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) की अभिकल्पना लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्त व्यवस्था और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने और समान गतिविधियों में लगी हुए संस्थाओं के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए की गई है । इसकी परिकल्पित भूमिका व्यापक है । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 250 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी के साथ 2 अप्रैल, 1990 को कार्य शुरु किया और इसने लघु उद्योग विकास निधि (एस.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 31 मार्च,1990 तक की स्थित के अनुसार 4200 करोड़ रुपए की राशि के बकाया पोर्टफोलियो को अधिगृहीत किया । बैंक की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी को बाद में बढ़ाकर क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 450 करोड़ रुपए कर दिया गया ।

एस. आई. डी. बी. आई. से संबंधित बजट प्रावधान राष्ट्रीय इक्विटी निधि (एनईएफ) के अंतर्गत सरकार से इक्विटी सहायता के लिए हैं :

| | | | (कराड़ रुपए) |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
| अनुदान | 24.00 | 21.18 | 22.00 |

अफ्रीकी विकास निधि/अफ्रीकी विकास बैंक

भारत अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक का सदस्य है । इन दोनों सगंठनों में हमारी सदस्यता के कारण भारत अफ्रीकी महाद्वीप के विकासशील देशों के साथ अधिक निकटता से सहयोग कर पाएगा तथा उनके प्रयासों में योगदान दे पाएगा । माल और सेवाओं के भारतीय नियार्तकों को अफ्रीका के क्षेत्रीय सदस्य देशों में विभिन्न ऐसी विकास परियोजनाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोली देने का लाभ प्राप्त होता है जिनका वित्तपोषण अफ्रीकी विकास निधि/अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा किया जाता है । ब. अ. 2004-2005 के लिए अफ्रीकी विकास निधि/बैंक के लिए बजटीय प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 9.08 | 9.03 | 0.85 |

एशियाई विकास बैंक पष्ठभमि

आर्थिक विकास की उपयुक्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए दिसम्बर, 1966 में एक प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्था एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय मनीला में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य होने के अलावा इसके पूंजी स्टाक में जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य के बाद चौथा सबसे बड़ा अंशदाता है।

| | | | (Rs. in crores) |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
| Grants | ••• | 50.00 | 37.50 |
| Non-Counter part for | | | |
| Exchange variation | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is designed to function as the principal financial institution for the promotion, financing and development of industry in the small scale sector and co-ordinate the functions of institutions engaged in similar activities. The role envisaged is wide ranging. SIDBI became operational on 2.4.1990 with an initial paid up capital of Rs.250 crores and taking over the outstanding portfolio of IDBI relating to small scale sector held under the Small Industries Development Fund (SIDF) as on March 31, 1990 amounting to Rs.4200 crores. The authorised capital and paid up capital of the Bank were subsequently raised to Rs.500 crores and Rs.450 crores respectively.

Budget Provisions relating to SIDBI are for equity support from the Government under National Equity Fund (NEF):

(Rs. in crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 24.00 | 21.18 | 22.00 |

AFRICAN DEVELOPMENT FUND/AFRICAN DEVELOPMENT BANK

India is a member of the African Development Fund as well as African Development Bank. Our membership of these two organisations will enable India to cooperate more closely with the developing countries of the African continent and to contribute to their efforts. Indian exporters of goods and services shall have the benefit of bidding against procurement for variety of development projects in the regional member countries of Africa that are financed by the African Development Fund/African Development Bank. Budgetary provision for African Development Fund/Bank are as under:-

(Rs. in crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 9.08 | 9.03 | 0.85 |

ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

Background

The Asian Development Bank, a major regional financial institution, was established in December, 1966 with its headquarters at Manila to accelerate economic and social development in the Asia and the Pacific region by providing financial and technical assistance for suitable projects for the economic development. India besides being its founder member, is the fourth largest contributor to its capital stock after Japan, USA and People's Republic of China.

ऋण

यद्यपि भारत, एशियाई विकास बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के तहत उधार लेने के लिए पात्र है, फिर भी उसने स्वेच्छा से वर्ष 1986 तक, जब यह निर्णय ले लिया गया कि हमारे संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंक से उधार लेना शरु किया जाए, उधार नहीं लिया।

एशियाई विकास बैंक में निवेश

ए.डी.बी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा दिनांक 22 मई, 1994 को पारित संकल्प सं. 232 के अनुसार बैंक को अपने प्राधिकृत पूंजी स्टॉक में 100 प्रतिशत की और वृद्धि करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रस्तावित वृद्धि शृंखला में चौथे स्थान पर है। मारत का हिस्सा 112,005 शेयर होंगे जिनमें से 2240 का शेयरों के रूप में भुगतान किया जाएगा और शेष 109,765 प्रतिदेय शेयर होंगे। इस प्रयोजन हेतु, एशियाई विकास बैंक में निवेश करने के लिए बजट अनुमान 2004-2005 में 6.51 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसे सं.अ. 2004-05 और 2005-06 में वही रखा गया है।

तकनीकी सहायता विशेष निधि

एशियाई विकास बैंक द्वारा तकनीकी सहायता विशेष निधि का उपयोग भारत और अन्य सदस्य देशों के परामर्शदाताओं की सेवाओं पर भुगतान हेतु किया जाता है। भारत वर्ष 1970 से इस निधि में स्वेच्छा से अंशदान दे रहा है। इस प्रयोजन हेतु बजट अनुमान 2005-2006 में 23 लाख रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव मांग सं. 32 में किया गया है।

भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड (एससीआईसीआई)

3 अप्रैल, 1987 से नौवहन विकास निधि समिति के समापन के परिणामस्वरूप भूतपूर्व नौ. वि. नि. स. की समस्त परिसंपत्तियां तथा देयताएं केन्द्र सरकार के अधीन हैं। भूतपूर्व नौ. वि. नि. स. जहाजों के अधिग्रहण के लिए नौवहन कंपनियों को वित्तीय सहायता देती आ रही थी। भूतपूर्व नौ. वि. नि. स. की शेष प्रतिबद्धताओं को सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। ब.अ. 2004-05 में इस प्रयोजनार्थ 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जिसे सं.अ. 2004-05 व ब.अ. 2005-06 में वही रखा गया है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

1. पृष्टभूमि

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए आधार स्तर की वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्तपोषण सहायता देता रहा है। नाबार्ड की स्थापना 100 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी से, जिसमें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रमशः 50:50 का अंशदान दिया था, जुलाई, 1982 में हुई थी।

एकीकृत ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने की दृष्टि से कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम्य उद्योगों, हस्तकलाओं तथा अन्य ग्रामीण कलाओं और अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए 'नाबार्ड' एक शीर्ष संस्थान है।

2. निधियों के स्रोत

सरकार नाबार्ड को, आई. डी. ए,, आई. बी. आर. डी. तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं के तहत प्राप्त ऋण सहायता की समतुल्य रुपया राशि देती रही है। सरकार द्वारा नाबार्ड को ये प्रतिरूप निधियां दाता देशों के साथ हुए अलग-अलग करारों में की गई व्यवस्था के अनुसार ऋणों और अनुदानों के रूप में अंतरित की जाती हैं।

'आयोजना-भिन्न' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को दी जाने वाली सहायता को विदेशी अभिकरणों से प्राप्त ऋण से संबंधित रुपया प्रतिरूप निधियों की सीमा तक ही दिया जा रहा है।

Loans

Although eligible to borrow under the criteria laid down by the ADB, India voluntarily refrained from borrowing until 1986, when in order to broad base our resources it was decided to commence borrowings from the Bank.

Investment in ADB

In terms of Resolution No.232 adopted by the Board of Governors of the ADB on 22nd May, 1994 the Bank has been empowered to make further increase of 100% in its authorised capital stock. The proposed increase is fourth in the series. India's share will be 112,005 shares of which 2240 will be paid in shares and the balance 109,765 will be callable shares. For this purpose a provision of Rs.6.51 crores was made in B.E. 2004-2005 for investment in ADB which has been retained in RE 2004-05 and BE 2005-06.

Technical Assistance Special Fund

The Technical Assistance Special Fund is utilised by the Asian Development Bank for payment in the services of the consultants from India and other member countries. India has been contributing to this Fund voluntarily since 1970. A provision of Rs.23.00 lakhs has been proposed in B.E. 2005-2006 for this purpose in Demand No.32.

SHIPPING CREDIT & INVESTMENT COMPANY OF INDIA LIMITED (SCICI)

Consequent upon abolition of the Shipping Development Fund Committee with effect from 3rd April, 1987, all assets and liabilities of erstwhile SDFC vest in the Central Government. The erstwhile SDFC had been granting financial assistance to shipping companies for acquisition of ships. The balance commitments of erstwhile SDFC have to be met by Government. A provision of Rs. 0.01 crore was made for the purpose in BE 2004-05, which has been retained in RE 2004-05 and BE 2005-06.

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (NABARD)

1 Background

The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is providing refinance support to base level financial institutions for lending to rural sector. NABARD was set up in July, 1982 with a share capital of Rs.100 crores contributed by Government of India and Reserve Bank of India on 50:50 basis.

NABARD is an apex institution for providing credit for the promotion of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts, and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity in rural areas.

2. Sources of Funds

The Government has been providing to NABARD the rupee equivalent to the credit assistance received by it under various IDA, IBRD and bilateral projects. These counterpart funds are passed on to NABARD by the Government as loans and grants as provided in the respective agreements entered into with the donor countries.

Under 'Non-Plan', the support by the Government of India to NABARD is being extended only to the extent of the Rupee Counterpart Funds relating to credit from external agencies.

| | | | (करोड़ रुपए) |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
| विदेशी सहायता प्राप्त संघटक | | | |
| को अनुदान (आयोजना-भिन्न) | 5.30 | 5.30 | 5.18 |
| सहकरी ऋण संरचना को सुदृढ़ | | | |
| करने के लिए अनुदान | 800.00 | 200.00 | 600.00 |

जल संचयन योजना के लिए अनुदान

आयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्र-व्यापी जल संचयन योजना हेतु आसान शर्तों पर धन उधार देने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजनार्थ नाबार्ड के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पचास प्रतिशत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

| / 1 | 1 |
|--------|--------|
| (करांड | जागा। |
| 19/10 | (/9(.) |

| | | | (4, (19, 1, 13) |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
| जल संचयन योजना हेतु | ••• | 5.00 | 3.81 |
| नाबार्ड की अनुदान | | | |
| (आयोजना) | | | |

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास-वित्त संबंधी गतिविधियों में एक शीर्ष निकाय के रूप में जुलाई, 1988 से कार्य आरम्भ किया। इसका लक्ष्य आवास-वित्त हेतु न केवल एक मजबूत संस्थागत ढांचा मुहैया कराना है बिल्क विशेष रूप से आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वास्तविक संसाधनों तथा बचतों की आपूर्ति में वृद्धि करना भी है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

| (कराड़ | रुपए) |
|--------|-------|
| | |

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| विनिमय (आयोजना-भिन्न) | 7.70 | 7.48 | 7.70 |
| अंतर | | | |

स्ट्रेस्ड आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के लिए आस्ति प्रबंधन न्यास

इस प्रयोजन हेतु ब.अ. 2004-05 (आयोजना-भिन्न) में 9000.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है और इसे सं.अ. 2004-05 में यही रखा गया है। ब.अ. 2005-06 में इस प्रयोजनार्थ कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऋणों पर ब्याज की दर में छूट के बदले आईआईबीआई और गांव बेंकों को दी गई सब्सिडी निम्नानुसार है:

| / | ٦ | |
|-----|-----|------|
| 12h | ਹੀਟ | 5577 |
| | | |

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| आईआईबीआई (आयोजना-भिन्न) | 143.00 | 143.00 | 0.00 |
| गांव बैंक | 0.09 | 0.09 | 0.08 |

एक्ज़िम बैंक की शेयर पूंजी को अभिदान

इस प्रयोजनार्थ, ब.अ. 2004-05 (आयोजना-भिन्न) में 200.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी, जिसे सं.अ. 2004-05 और ब.अ. 2005-06 में वही रखा गया है।

| | | | (Rs in Crores) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
| Grants to External aided component (Non-Plan) | 5.30 | 5.30 | 5.18 |
| Grants for strengthening the Cooperative Credit Structure | 800.00 | 200.00 | 600.00 |

Grant for Water Harvesting Scheme

Under Plan, the provision has been made for lending money on easy terms for nation-wide Water Harvesting Scheme belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Fifty percent Capital subsidy is being provided by the Central Government through NABARD for the purpose.

(Rs. in Crores)

| | | | (, |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
| Grants to NABARD for | ••• | 5.00 | 3.81 |
| Water Havesting Scheme | | | |
| (Plan) | | | |

NATIONAL HOUSING BANK (NHB)

The National Housing Bank (NHB) commenced its operations from July,1988 as an apex body in the housing finance activities. Its aim is not only to provide a sound institutional framework for the housing finance but also to augment the supply of real resources and savings specifically to meet housing needs.

The Budget provision for NHB is as under:-

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Exchange (Non Plan) | 7.70 | 7.48 | 7.70 |
| Variation | | | |

ASSET MANAGEMENT TRUST FOR STRESSED ASSETS STABILISATION FUND (SASF)

A sum of Rs. 9000.00 crore was provided for this purpose in BE 2004-05 (Non-Plan) and the same has been retained in RE 2004-05. No provision has been made in BE 2005-06 for this purpose.

Subsidy in lieu of concession in the rate of interest on loans has been provided to IIBI and Goan Banks as under:-

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| IIBI (Non-Plan) | 143.00 | 143.00 | 0.00 |
| Goan Banks | 0.09 | 0.09 | 0.08 |

SUBSCRIPTION TO THE SHARE CAPITAL OF EXIM BANK

An amount of Rs. 200.00 crore was provided for the purpose in BE 2004-05 (Non-Plan), which has been retained in RE 2004-05 and BE 2005-06.

आईआईबीआई के इक्विटी/अधिमानी शेयरों को अभिदान

ब.अ. 2005-06 (आयोजना-भिन्न) के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु 750.00 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है।

गारंटी प्रतिदान निधि

यह अंशदान गारंटी प्रतिदान निधि की संचित निधि के निर्माण के लिए हैं। इस निधि के लिए निम्नलिखित बजटीय व्यवस्था की गई है:

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 125.00 | 125.00 | 125.00 |

भारत सहस्त्राबदि खातों पर विनिमय हानि के लिए अंशदान

भारत सहस्त्राबदि खातों पर विनिमय हानि की पूर्ति हेतू निम्नलिखित बजटीय प्रावधान किए गाए हैं :

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 208.00 | 0.00 | 1.00 |

जारी की जा चुकी भारतीय यूनिट ट्रस्ट प्रतिभुतियों के लिए सहायता

यह प्रावधान संबद्ध वर्षों के दौरान परिपक्व होने वाली आश्वासित प्रतिफल योजनाओं में गिरावट की पूर्ति के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) की सहायता का द्योतक है। इस प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बजटीय प्रावधान किए गए है:-

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |

वरिष्ठ पंशन बीमा योजना (वीपीबीवाए)

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को 8 जुलाई, 2004 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, पहले ही जारी की जा चुकी और परिपक्व हो रही पाँलिसियों संबंधी पेंशन वार्षिकी के दायित्वों की पूर्ति के लिए निम्नानुसार बजटीय व्यवस्था की गई है:-

(करोड रुपए)

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 150.00 | 263.16 | 269.19 |

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि में अंशदान (आईएफएडी)

यह प्रावधान आईएफएडी में भारत के अंशदान का द्योतक है। निम्नलिखित प्रावधान किए गए है:-

(करोड रुपए

| | ब. अ. 2004-2005 | सं. अ. 2004-2005 | ब. अ. 2005-2006 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| अनुदान | 23.00 | 22.745 | 23.00 |

SUBSCRIPTION TO EQUITY/PREFERENCE SHARES OF IIBI

A budgetary provision of Rs. 750.00 crore has been made for the purpose under BE 2005-06 (Non-Plan)

GUARANTEE REDEMPTION FUND

The contribution is for building up the corpus of the Guarantee Redemption Fund. The following budgetary provisions have been made for this fund:

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 125.00 | 125.00 | 125.00 |

CONTRIBUTIOIN TOWARDS EXCHANGE LOSS ON INDIA MILLENIUM DEPOSITS

The following budgetary provision have been made to cover exchange losses on India Millennium Deposits:-

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 208.00 | 0.00 | 1.00 |

ASSISTANCE FOR UNIT TRUST OF INDIA SECURITIES ISSUED

This represents provision for assistance to Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to meet the shortfall in the Assured Return Schemes (ARS) maturing during the relevant years. The following budgetary provisions have been made for the purpose:

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |

VARISHTHA PENSION BIMA YOJANA (VPBY)

Varishtha Pension Bima Yojana has been discontinued w.e.f. 8th July, 2004. however, the budgetary provisions as under have been made to meet liabilities towards pension annuity in respect of policies already issued and maturing:

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 150.00 | 263.16 | 269.19 |

CONTRIBUTION TO INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)

The provision represents India's contribution to IFAD. The following provisions have been made:

(Rs. in Crores)

| | B.E. 2004-2005 | R.E. 2004-2005 | B.E. 2005-2006 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| Grants | 23.00 | 22.745 | 23.00 |

मांग संख्या 39 व्यय विभाग

(i) मुख्य शीर्ष "2052"

यह प्रावधान विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए है ।

(ii) मुख्य शीर्ष "2070"

1.40 करोड़ रुपए का प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्ध सोसाइटी संस्थान को सहायता प्रदान करने के लिए हैं ।

विशेष श्रेणी राज्यों के वित्त एवं लेखा मामलों से संबंधित अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान में एम.बी.ए (वित्त) के बुनियादी तत्वों को शामिल करने वाले पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा कोर्स में 15 सीटों के लिए वित्तपोषण करने हेत 0.50 करोड़ रुपए का आयोजना प्रावधान किया गया है।

महालेखा नियंत्रक के संगठन द्वारा सिविल लेखा विभाग के समूह 'ख' और 'ग' कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए स्थापित सरकारी लेखा और वित्त संस्थान की संस्थापना और अन्य व्यय को पूरा करने के लिए 1.15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एशियाई सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान के लिए 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

मांग संख्या 42 राजस्व विभाग

(करोड़ रुपए)

| | बजट | संशोधित | बजट |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2052 | 43.01 | 54.72 | 71.81 |

यह व्यवस्था केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त आसूचना एकक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम तथा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण सहित राजस्व विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए हैं।

- 2. यह व्यवस्था 12 विशेष श्रेणी तथा नवसृजित राज्यों के संबंध में मूल्य वर्द्धित कर की और अंतरण के अंततः उद्देश्य से बिक्री कर विभाग की अवसंरचना के सशक्तीकरण के लिए की गई है।
- 3. मूल्य वर्द्धित कर की शुरुआत के संबंध में 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को जोड़ने के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान के रूप में उपकरणों की खरीद आदि तथा अधिकार प्राप्त समिति/वैट परिषद की बैठकों के आयोजन के लिए विविध व्ययों के लिए व्यवस्था की गई है।

DEMAND NO.39 DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(i) Major Head "2052"

The provision is for Secretariat Expenditure for the Department.

(ii) Major Head "2070"

The provision of Rs.1.40 crores is for grant of assistance to National Institute of Financial Management Society.

Plan provision of Rs.0.50 crore is made for funding 15 seats in Post Graduate Diploma course in NIFM covering basic elements of MBA (Finance) for the officers of Special Category states dealing with Finance & Accounts matters.

Provision of Rs. 1.15 crore is to meet the establishment and other expenditure of Institute of Government Accounts & Finance set up to provide training facilities for Group 'B' & 'C' employees of Civil Accounts Department by the Organisation of Controller General of Accounts. A provision of Rs.0.01 crore is for contribution to Association of Government Accounts Organisation of Asia.

DEMAND NO.42 DEPARTMENT OF REVENUE

(Rs. in crores)

| Major Head | Budget | Revised | Budget |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Estimates 2004-2005 | Estimates 2004-2005 | Estimates 2005-2006 |
| | | | |

The provision is for Secretariat Expenditure of the Department of Revenue including the Central Economic Intelligence Bureau , Financial Intelligence Unit and Competent Authority under Smugglers and Foreign Exchange Manipulation (Forefeiture of Property) Act and Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act.

- 2. The provision has also been made for strengthening of infrastructure of Sales Tax Department with the ultimate objective of switching over to a Value Added Tax in respect of 12 Special Category and newly created States.
- 3. The provision has also been made for setting up of a Tax Information Exchange System(TINXSYS) for connecting 28 States and Union Territories in connection with the introduction of Value Added Tax System. In addition, provision has been made for purchase of equipments etc. and for miscellaneous expenses for holding meetings of Empowered Committee/VAT Council as grant in aid.

| | | | (करोड़ रुपए) |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | बजट | संशोधित | बजट |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2020 | 0.36 | 0.30 | 0.36 |

यह व्यवस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत गठित आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति के व्ययों की पूर्ति के लिए की गई है।

| / 7 | L . | ١. |
|------|-----|-------|
| (करा | ~ | रुगा। |
| | | |

| | बजट | संशोधित | बजट |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2045 (1) | | | |
| (अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर) | 36.00 | 35.00 | 3.00 |

अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर, जो 1989-90 में शुरु किया गया था, देशीय हवाई यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से उद्ग्रहणीय है। यह कर कैरियरों, यथा इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया, वायुदूत और पवन हंस लि. द्वारा एकत्र किया जाता है। यह व्यवस्था कैरियरों को संग्रहण प्रभारों जो संगृहित कर के 5% की दर पर आकलित किया जाता है, की अदायगी के संबंध में की गई है।

(करोड़ रुपए)

| | | | , , , |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | बजट | संशोधित | बजट |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2045 (2) | 1.00 | 0.90 | 0.45 |
| (विदेश यात्रा कर) | | | |

विदेश यात्रा कर किसी यात्री द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में देय होता है। यह कर कैरियरों द्वारा एकत्र किया जाता है जिसके लिए एकत्रित करों के 1/3% संग्रहण प्रभार उन्हें अदा किए जाते हैं। यह व्यवस्था ऐसे प्रभारों की अदायगी के लिए है।

(करोड रुपए)

| | | | 1 . " |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | बजट | संशोधित | बजट |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2047 (1) | 18.40 | 17.40 | 19.00 |

यह व्यवस्था प्रवर्तन निदेशालय जो विदेशी मुद्रा छलसाधन अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित है, के व्यय के लिए हैं ।

(Rs in crores)

| | | | (Its. in crores) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Budget | Revised | Budget |
| Major Head | Estimates | Estimates | Estimates |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2020 | 0.36 | 0.30 | 0.36 |

The provision is for meeting the expenses of the National Committee for Promotion of Economic & Social Welfare set up under the Income Tax Act.

(Rs. in crores)

| Major Head | Budget Estimates 2004-2005 | Revised Estimates 2004-2005 | Budget Estimates 2005-2006 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2045 (1) | | | |
| (Inland Air Travel Tax) | 36.00 | 35.00 | 3.00 |

Inland Air Travel Tax, which was introduced in 1989-90 is leviable on all passengers embarking for domestic air journey. The tax is collected by the carriers, viz. Indian Air lines, Air India, Vayudoot and Pawan Hans Ltd. The Provision is for payment of the collection charges to the carriers, which is worked out at the rate of 5% of the tax collected.

(Rs. in crores)

| Major Head | Budget Estimates 2004-2005 | Revised Estimates 2004-2005 | Budget Estimates 2005-2006 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2045 (2) | 1.00 | 0.90 | 0.45 |
| (Foreign Travel Tax) | | | |

The Foreign Travel Tax is payable in respect of an international journey undertaken by a passenger. The tax is collected by the carriers for which collection charges at 1/3% of the tax collected are paid to them. The provision is for the payment of such charges.

(Rs. in crores)

| | Budget | Revised | Budget |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| Major Head | Estimates | Estimates | Estimates |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2047 (1) | 18.40 | 17.40 | 19.00 |

The provision is for expenditure of the Enforcement Directorate which is concerned with the enforcement of Foreign Exchange Manipulation Act.

| | | | (कराड़ रुपए) |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | बजट | संशोधित | बजट |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2047 (2) | 2.06 | 1.96 | 2.06 |

यह व्यवस्था राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के कर्मचारियों के लिए वेतनमान और मंहगाई भत्ते में संशोधन की वजह से हुए आवर्ती किस्म के व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को सहायता अनुदान देने के लिए की गई है।

(करोड रुपए)

| | बजट | संशोधित | बजट |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2047 (3) | 0.18 | 0.28 | 0.28 |

यह प्रावधान मनी लांड्रिंग के संबंध में एशिया/प्रशांत समूह के सदस्य के रूप में अंशदान के लिए है।

(करोड रुपए)

| | बजट | संशोधित | बजट |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2047 (4) | 9.32 | 9.16 | 10.97 |

इसमें तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए व्यवस्था की गई है।

(करोड रुपए)

| | बजट | संशोधित | बजट |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| 3 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2070 (1) | 18.09 | 17.98 | 18.78 |

इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के लिए व्यवस्था शामिल है।

(करोड़ रुपए)

| 2070 (2) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | बजट | संशोधित | बजट |

यह व्यवस्था मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र निधि, कर-प्रशासकों के राष्ट्रमण्डलीय संघ, सीमा-शुल्क परिषद और कोलम्बो योजना ब्यूरों के औषधि परामर्शी कार्यक्रम को दिए जानेवाले अंशदान हेतु की गई है।

| | | | (Ns. in crores) |
|------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Revised | Budget |
| Major Head | Estimates | Estimates | Estimates |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2047 (2) | 2.06 | 1.96 | 2.06 |

The provision is for grant-in-aid to the National Institute of Public Finance & Policy for meeting recurring type of expenditure on account of revision in the pay scales and D.A. for the employees of the National Institute of Public Finance & Policy.

(Rs. in crores)

| | Budget Estimates 2004-2005 | Revised Estimates 2004-2005 | Budget |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Major Head | | | Estimates |
| | | | 2005-2006 |
| 2047 (3) | 0.18 | 0.28 | 0.28 |

The provision is for contribution as a Member of Asia/Pacific Group on Money Laundering.

(Rs. in crores)

| | Budget Estimates 2004-2005 | Revised Estimates 2004-2005 | Budget Estimates 2005-2006 |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Major Head | | | |
| | | | |

This includes provisions for Appellate Tribunal under Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Central Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal.

(Rs. in crores)

| Major Head | Budget | Revised | Budget |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Estimates | Estimates | Estimates |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2070 (1) | 18.09 | 17.98 | 18.78 |

This includes provision for Central Bureau of Narcotics.

(Rs. in crores)

| Major Head | Budget | Revised | Budget |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | Estimates 2004-2005 | Estimates 2004-2005 | Estimates |
| | | | 2005-2006 |
| 2070 (2) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |

This provision is for contributions to United Nations Fund for control of Drug Abuse, Commonwealth Association of Tax Administrators, Customs Council and Drug Advisory Programme of Colombo Plan Bureau.

| | | | (करोड़ रुपए) |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | बजट | संशोधित | बजट |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2070 (3) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग निधि को अंतरण के लिए प्रावधान किया गया है।

(करोड रुपए)

| | बजट | संशोधित | बजट |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2875 | 261.57 | 270.21 | 245.85 |

यह अफीम की फसल की खरीद सहित गाजीपुर और नीमच में अफीम के कारखानों और अल्कलॉयड वर्क्स के व्यय का द्योतक है। केन्द्रीय सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण नियंत्रण है और वह चिकित्सीय और वैज्ञानिक जरुरतों के लिए इसे संसाधित करने और बेचने हेतु समस्त उपज खरीद लेती है।

(करोड रुपए)

| | | | . , , |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | बजट | संशोधित | बजट |
| मुख्य शीर्ष | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 3601 | ••• | ••• | 5000.00 |

यह प्रावधान मूल्य वर्द्धित कर की पुरः स्थापना के कारण राज्यों को हुई राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए है।

(करोड रुपए)

| मुख्य शीर्ष | बजट | संशोधित | बजट |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| पूंजी 4216 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

इसमें प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के लिए बने बनाए फ्लैटों के क्रय के लिए व्यवस्था की गई है।

(करोड रुपए)

| मुख्य शीर्ष | बजट | संशोधित | बजट |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 4875 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |

यह गाजीपुर तथा नीमच में अफीम के कारखानों तथा अल्कालॉयड कार्य के संबंध में पूंजी व्यय का द्योतक है। (Rs. in crores)

| | Budget | Revised | Budget Estimates 2005-2006 |
|------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Major Head | Estimates 2004-2005 | Estimates 2004-2005 | |
| | | | |

The provision is for Transfer to National Fund for Control of Drug Abuse.

(Rs. in crores)

| | Budget | Revised | Budget | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| Major Head | Estimates | Estimates | Estimates | | |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 | | |
| 2875 | 261.57 | 270.21 | 245.85 | _ | |

This represents the expenditure of the Opium Factories and Alkaloid works at Ghazipur and Neemuch including purchase of Opium produce. Central Government exercises exclusive control over the cultivation of Opium and purchases the entire produce for processing and sale for medicinal and scientific needs.

(Rs. in crores)

| | Budget | Revised | Budget | | |
|------------|-----------|------------------|------------------|--|--|
| Major Head | Estimates | Estimates | Estimates | | |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 | | |
| 3601 | | | 5000.00 | | |

The provision is for Compensation to States for revenue losses due to Introduction of Value Added Tax.

(Rs. in crores)

| Major Head | Budget Estimates 2004-2005 | Revised Estimates 2004-2005 | Budget Estimates 2005-2006 | |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Capital | | | | |
| 4216 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

The provision is for purchase of ready built flats for the employees of Enforcement Directorate.

(Rs. in crores)

| | Budget | Revised | Budget | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Major Head | Estimates 2004-2005 | Estimates 2004-2005 | Estimates 2005-2006 | | |
| 4875 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |

This represents the Capital Expenditure in respect of Opium Factories and Alkaloid works at Ghazipur and Neemuch.

मांग संख्या Demand No.43 प्रत्यक्ष कर DIRECT TAXES

वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है: The Budget Allocations net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

| | | | बजट अनुमान | | ₹ | शोधित अनुमान | | ब | जट अनुमान | |
|--|-------------|--------|--------------|---------|--------|--------------|---------|--------|--------------|---------|
| | | | lget 2004-0 |)5 | | vised 2004-0 |)5 | | dget 2005-06 | |
| | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | Major Head | Plan | Non-Plan | Total | Plan | Non-Plan | Total | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व Re | | ••• | 1145.98 | 1145.98 | ••• | 1169.93 | 1169.93 | ••• | 1166.00 | 1166.00 |
| पूंजी C | apital | ••• | 100.00 | 100.00 | | 55.07 | 55.07 | ••• | 82.00 | 82.00 |
| जोड़ 🛚 | Γotal | | 1245.98 | 1245.98 | | 1225.00 | 1225.00 | | 1248.00 | 1248.00 |
| आय और व्यय पर करों का संग्रह | | | | | | | | | | |
| Collection of Taxes on income and Expenditure | | | | | | | | | | |
| 1. आय कर का संग्रह Collection of Income Tax | 2020 | | 898.83 | 898.83 | | 917.62 | 917.62 | | 914.53 | 914.53 |
| 2. निगम कर का संग्रह Collection of Corpn. Tax | 2020 | | 138.28 | 138.28 | | 141.17 | 141.17 | | 140.70 | 140.70 |
| 3. व्यय कर का संग्रह Collection of Expr. Tax | 2020 | | 5.16 | 5.16 | | 5.27 | 5.27 | | 5.25 | 5.25 |
| 4. ब्याज कर का संग्रह Collection of Int. Tax | 2020 | | 5.73 | 5.73 | | 5.85 | 5.85 | | 5.83 | 5.83 |
| 5. आधिक्य कर के प्रतिदायों पर ब्याज Interest on Refund of Ex | cess Tax | | | | | | | | | |
| संपदा शुल्क, धनकर और उपहार कर का संग्रह | | | | | | | | | | |
| Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth & Gift | Tax | | | | | | | | | |
| 6. धनकर का संग्रह Collection of Wealth Tax | 2031 | | 91.68 | 91.68 | | 93.59 | 93.59 | | 93.28 | 93.28 |
| 7. अन्य करों का संग्रह Collection of other Taxes | 2031 | | 6.3 | 6.3 | | 6.43 | 6.43 | | 6.41 | 6.41 |
| 8. तैयार निर्मित आवास की खरीद | | | | | | | | | | |
| Purchase of Ready Built Accommodation | | | | | | | | | | |
| 8.01 कार्यालय भवन Office Building | 4059 | | 80.00 | 80.00 | | 69.00 | 69.00 | | 66.00 | 66.00 |
| 8.02 आवासीय भवन Residential Building | 4216 | | 20.00 | 20.00 | | 16.66 | 16.66 | | 16.00 | 16.00 |
| | Total | | 100.00 | 100.00 | | 85.66 | 85.66 | | 82.00 | 82.00 |
| 9. आयकर अधिनयम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण | | | | | | | | | | |
| Acquisition of Immovable Property under Income | Tax Act | | | | | | | | | |
| 9.01 सकल व्यय Gross Expenditure | 4075 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| 9.02 घटाइए-बिक्री प्राप्तियां Less Sale Proceeds | 4075 | | -2.00 | -2.00 | | -32.59 | -32.59 | | -2.00 | -2.00 |
| निवल Net | | | 0.00 | 0.00 | | -30.59 | -30.59 | | 0.00 | 0.00 |
| कुल जोड़ GRAND TOTAL | | | 1245.98 | 1245.98 | | 1225.00 | 1225.00 | | 1248.00 | 1248.00 |

- 1-7. इस मांग में आयकर विभाग की आवश्यकता के लिए प्रावधान है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए तथा इकटठे किए गए सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आय पर कर (कार्पोरेट क्षेत्र की आय शामिल है), सम्पदा शुल्क, धन कर और उपहार कर संबंधी कार्य को प्रशासित करता है। संग्रहण के प्रयोजनार्थ देश को कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस विभाग में बड़े पैमाने पर अपवंचन के मामलों की छानबीन करने, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन के लिए पृथक निदेशालय भी हैं।
- (ख) विभाग ने राष्ट्रीय कम्प्यूटर सेंटर, दिल्ली में एकल डाटाबेस पर 510 शहरों में सभी आयकर कार्यालयों को जोड़ते हुए अखिल भारतीय आयकर नेटवर्क की स्थापना की अभिकल्पना करते हुए व्यापक कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम शुरु किया है। नेटवर्क की स्थापना और एकल डाटाबेस से विभाग कस्टमाइजड आयकर आवेदन साफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरों पर सभी आयकर विवरणियों के प्रक्रियान्वयन में समर्थ होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने टीडीएस विवरणियों को इलैक्ट्रानिक रूप से दर्ज करने के लिए मैसर्स नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सहायता से कर सूचना नेटवर्क की स्थापना की है जो बैंकों और टीडीएस प्रमाणपत्र के अभौतिकीकरण के माध्यम से कर अदायगियों संबंधी आन-लाईन सूचना प्राप्त कर रहा है। कर सूचना नेटवर्क करदाताओं को अपनी कर अदायगियों और वापसी अदायगियों के ब्योरे जानने के लिए अंतरापृष्ठ की अनुमति भी देगा। विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन की गति बढ़ाने के लिए मैसर्स यूटीआईआईएसएल और मैसर्स एनएसडीएल की सेवाएं आवेदन प्राप्त करने, डाटा एंट्री करने और विभाग को आनलाईन डाटा का संप्रेषण करने के लिए ली गई है।
- 8. यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के संबंध में तैयार-निर्मित कार्यालय भवनों और तैयार-निर्मित आवासीय भवनों की खरीद से संबंधित है।
- 9. यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में यथा परिकल्पित, केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों को पूर्वक्रयाधिकार के अनुसार खरीदने से संबंधित है। ऐसे क्रयों का आदेश निर्धारित सीमा से अधिक स्पष्ट प्रतिफल वाली संपत्तियों के संबंध में समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के इस अध्याय को 1.7.2002 से समाप्त कर दिया गया है। ब.अ. 2005-06 में इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पहले से अर्जित सम्पत्तियों के संबंध में वर्ष 2005-06 के लिए, संपत्तियों के रखरखाव तथा अनुरक्षण तथा सुरक्षा प्रभारों के लिए व्यवस्था की गई है।

मांग संख्या 44 अप्रत्यक्ष कर

(मुख्य शीर्ष - 2037- सीमाशुल्क, 2038 - संघ उत्पाद शुल्क, 2216-आवास-रखरखाव तथा मरम्मत,4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, 4059 - लोक निर्माण कार्य तथा 4216 - आवास)

आयोजना-भिन्न व्यय (सकल)

(हजार रुपए)

| | | | (0.11.1.13) |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | बजट अनुमान |
| | 2004-2005 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 2037 | 483,10,00 | 491,65,00 | 515,22,00 |
| 2038 | 779,50,00 | 833,57,00 | 942,95,00 |
| 2216 | 50,00 | 1,00,00 | 1,50,00 |
| 4047 | 173,83,00 | 26,40,00 | 135,73,00 |
| 4059 | 10,00,00 | 10,00,00 | 33,00,00 |
| 4216 | 15,00,00 | 15,00,00 | 20,00,00 |
| जोड़ | 1,461,93,00 | 1,377,62,00 | 1648,40,00 |
| स्वीकृत | 1,460,93,00 | 1,376,57,25 | 1,647,40,00 |

- 1-7. The Demand provides for the requirement of Income Tax Department, which administers all direct taxes levied and collected by the Central Government, namely, taxes on income (including income of the corporate sector, estate duty, wealth tax and gift tax. For the purpose of collection, the country has been divided into charges. The Department has also got separate Directorates for scrutiny of cases involving large scale evasion, inspection, research, statistics and publications.
- (b) The Department has undertaken programme of Comprehensive Computerisation envisaging setting up of All India Income Tax Network connecting all Income Tax Offices in 510 cities on a single database at National Computer Centre, Delhi. The setting up of Network and a single database would enable the Department to process all the income tax return on computers through customised Income Tax Application Software. In addition to this, the Department has also set up a **Tax Information Network (TIN)** with the help of M/s National Securities Depository Limited (NSDL) for electronic filing of TDS returns, receiving **On Line Information on Tax payments (OLTAS)** through banks and Dematerialisation of TDS Certificate. The Tax Information Network would also allow an interface to the taxpayers to know details of their tax payments and refunds. For expediting the allotment of **Permanent Account Numbers (PAN)** by the Department, services of M/s UTIISL and M/s NSDL have been obtained to receive the applications, do the data entry, and transmit the data online to Department.
- 8. The position relates to purchase of ready-built office building and ready-built residential buildings in respect of Direct Tax Organisation.
- 9. The provision relates to pre-emptive purchase of immovable properties by Central Government as envisaged in Chapter XXC of Income-tax Act, 1961. Such purchases are ordered by the Appropriate Authority in respect of properties having apparent consideration exceeding a prescribed limit. However, this chapter of I.T. Act, 1961 has been abolished since 1.7.2002. The provision in BE 2005-06 has been made for maintenance and upkeep of properties and security charges for the year 2005-06 in respect of properties already acquired by Central Government under this Act.

DEMAND NO.44 INDIRECT TAXES

(Major Head 2037 - Customs, 2038 - Union Excise Duties, 2216-Housing-Maintenance and Repairs, 4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services, 4059 - Public Works and 4216 - Housing)

Non Plan Expenditure (Gross)

(In thousands of rupees)

| Major Head | Budget Estimates 2004-2005 | Revised Estimates 2004-2005 | Budget Estimates 2005-2006 515,22,00 | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 2037 | 483,10,00 | 491,65,00 | | |
| 2038 | 779,50,00 | 833,57,00 | 942,95,00 | |
| 2216 | 50,00 | 1,00,00 | 1,50,00 | |
| 4047 | 173,83,00 | 26,40,00 | 135,73,00 | |
| 4059 | 10,00,00 | 10,00,00 | 33,00,00 | |
| 4216 | 15,00,00 | 15,00,00 | 20,00,00 | |
| Total | 1,461,93,00 | 1,377,62,00 | 1648,40,00 | |
| Voted | 1,460,93,00 | 1,376,57,25 | 1,647,40,00 | |

इस मांग में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है:-

- (i) सीमा शुल्क के स्थापना और अन्य व्यय, तस्कर-रोधी उपकरणों का रख-रखाव, रसायन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण आदि।
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग को छोटे पत्तनों पर उनके द्वारा किए गए सीमा-शुल्क संबंधी कार्य के लिए आनुपातिक प्रभारों का भुगतान।
- (iii) बाहर से आने वाले विदेशी पत्रों और पार्सलों पर लगने वाले सीमाशुल्क को एकत्र करने पर होने वाले स्वर्च के संबंध में डाक विभाग को कमीशन प्रभारों का भगतान।
- (iv) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कल्याण निधि, कार्य निष्पादन अवार्ड निधि और तस्कर-रोधी उपस्करों इत्यादि की अधिप्राप्ति हेत् सीमा शुल्क विशेष निधि के लिए अंशदान।
- (v) पूंजी भाग में समुद्री जहाजों और पोतों के अधिग्रहण तथा तस्कर-रोधी उपस्करों की अधिप्राप्ति के संबंध में सीमा शुल्क विभाग का व्यय।
- (vi) पूंजी भाग में सीमाशुल्क सीमा जांच चौकियों के लिए पूर्व-निर्मित परिसरों के निर्माण के लिए सीमाशुल्क विभाग का व्यय।
- (vii) सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के लिए तैयार निर्मित (गैर-आवासीय तथा आवासीय) आवास की खरीद।
- (viii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग की स्थापना तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों तथा सेवाकर को एकत्र करने के लिए इसके अन्य व्यय।
- (ix) विभागीय रिहायशी आवास का रख-रखाव तथा मरम्मत।

अभ्युक्तियां :- मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, कोचीन, बंगलौर, मंगलौर, अहमदाबाद, कान्डला और नाहवा शेवा स्थित प्रमुख पत्तनों में से प्रत्येक पत्तन में सीमा-शुल्क संबंधी प्रशासन कार्य प्रमुख सीमा-शुल्क आयुक्त/सीमा-शुल्क आयुक्त के प्रभाराधीन है। दिल्ली का सीमाशुल्क गृह भी प्रमुख सीमा-शुल्क आयुक्त (सामान्य/निवारक) के प्रभाराधीन है। इसके अलावा, कितपय स्थानों यथा मुम्बई, कोलकात्ता, पटना, लखनऊ, शिलाँग, अमृतसर, जोधपुर, त्रिची और पुणे के सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) के प्रभाराधीन है। अन्य स्थानों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग में संयक्त स्थापना है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग अनेक छोटे पत्तनों पर सीमा-शुल्क संबंधी कार्य भी करता है जिसके लिए सीमा-शुल्क विभाग से आनुपातिक प्रभार वसूल किए जाते हैं।

संशोधित अनुमान - 2004-2005

विषय शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत 42 करोड़ रुपए तथा सूचना प्रौद्योगिकी सिहत "कार्यालय व्यय" के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए, प्रचार के अंतर्गत 9.70 करोड़ रुपए का आधिक्य अनुमान है तथा वेतन तथा भत्तों में वृद्धि, नए आयुक्तालयों के सृजन, और अधिक केन्द्रों में इडीआई (सीमा शुल्क) कम्प्यूटरीकरण) के कार्यान्वयन तथा सेवा कर प्रावधानों के विस्तृत प्रचार पर व्यय, जिसमें से कुछ अन्य शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जा चुका है, के कारण अन्य शीर्षों में लघु वृद्धियां हुई हैं। राजस्व भाग में 63.12 करोड़ रुपए की समग्र वृद्धि है। पूंजी भाग में 147.43 करोड़ रुपए की बचत है।

Provision is made in this demand for: -

- i) Establishment and other expenditure of Customs, Maintenance of Anti-Smuggling Equipments, Modernisation of Chemical Laboratory etc.
- ii) Payment of proportionate charges to the Central Excise Department for Customs work done by it at Minor Ports.
- iii) Payment of Commission charges to Postal Deptt. towards the cost of collection of Customs Duty on inward foreign letters and parcels.
- iv) Contribution towards Customs & Central Excise Welfare Fund, Performance Award Fund and Customs Special Fund for acquisition of anti-smuggling equipments etc.
- Expenditure of Customs in Capital Section on Acquisition of Ships and Fleets and acquisition of Anti-Smuggling Equipments.
- vi) Expenditure of Customs Department in Capital Section for construction of pre-fabricated premises for Customs Border check-posts.
- vii) Purchase of ready-built (non-residential and residential) accommodation for Customs & Central Excise Departments.
- viii) Establishment of Central Excise Department and its other expenditure for collection of Union Excise Duties and Service tax.
- ix) Maintenance and Repairs of Departmental residential accommodation.
- Remarks: The Customs administration in each of the Major Ports at Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin, Bangalore, Mangalore, Ahmedabad, Kandla and Nhava Sheva is under the charge of Chief Commissioner/Commissioner of Customs. The Custom House at Delhi is also under the charge of the Chief Commissioner of Customs(General)/(Preventive) Commissionrates at certain places viz., Mumbai, Kolkata, Patna, Lucknow, Shillong, Amritsar, Jodhpur, Trichy and Pune are under the charge of Commissioner of Customs (Preventive). At other places there is combined establishment in the Central Excise Department.

The Central Excise Department also performs Customs work at various Minor Ports for which proportionate charges are recovered from the Customs Department.

REVISED ESTIMATE 2004-2005

There is excess projection of Rs. 42 crores under the Object Head 'Salaries' and Rs. 23 crores under 'Office Expenses', including Information Technology, Rs. 9.70 crores under 'Publicity and minor increases in other heads due to increase in salaries and allowances, creation of new Commissionerates, Implementation of EDI(Customs Computerization) in more centers and expenses on giving wide publicity to the Service Tax provisions some of which has been offset by savings under other heads. The overall increase is Rs. 63.12 crores in the Revenue Section. There is savings of Rs. 147.43 crores in the Capital Section.

बजट अनुमान 2005-2006

मुख्य शीर्ष 2038 के अंतर्गत वृद्धि मुख्यतया सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग में सूचना अवसंरचना परियोजना के समेकन के लिए 162.50 करोड़ रुपए की कुल लागत पर किए गए प्रावधानों के लिए है जिसे आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमोदित कर दिया है। परियोजन कार्यन्वयन 18 महीनों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चरणबद्ध तरीके से समुद्री बेड़े की अधिप्राप्ति के लिए, जिसे सीसीईए ने अनुमोदित कर दिया है व अन्य तरकर-रोधी उपस्करों की खरीद के लिए पूंजी भाग (मुख्य शीर्ष 4047) में 135.73 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

मांग संख्या - 45 विनिवेश विभाग

सरकार (संयुक्त मोर्चा) ने अगस्त 1996 में एक सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग की स्थापना की थी जिसे सरकार द्वारा उसे संदर्भित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार द्वारा किए जाने वाले विनिवेशों की आवश्यकता, विस्तार तथा तरीके के संबंध में सरकार को सलाह देने का अधिदेश प्राप्त था। इस आयोग का कार्यकाल नवंबर, 1999 में समाप्त हो गया। तत्पश्चात सरकार ने जुलाई, 2001 में पूर्व आयोग के समान अधिदेश के साथ ही विनिवेश आयोग का पुनर्गठन किया। आयोग का विस्तारित कार्यकाल 31 अक्तूबर, 2004 तक था।

2. जून, 2004 में अंगीकृत, वर्तमान सरकार (यूपीए) के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों का सुदृढ़ीकरण और लाभ कमाने वाले सार्वजिनिक क्षेत्र के उद्यमों का सामान्यता निजीकरण न किया जाना परिकित्पित है। वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्तुत करते समय, सरकार ने जुलाई 2004 में संसद में यह घोषणा की थी कि सरकार सार्वजिनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना करेगी। सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप विनिवेश आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उसे 1 नवम्बर, 2004 से समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् सरकार ने 6 दिसंबर, 2004 को सार्वजिनक उद्यम विभाग के अंतर्गत बीआरपीएसई का गठन किया है।

BUDGET ESTIMATES 2005-2006

The increase under Major Head 2038 is mainly on account of provisions made for the Consolidation of Information Infrastructure Project in the Customs and Central Excise Department at a total cost of Rs.162.50 crores which has been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) . The project implementation will be spread over 18 months. Further, a provision of Rs.135.73 crores has been made in the Capital Section (Major Head 4047) for procurement of Marine Fleet in a phased manner , which has also been approved by CCEA and for procurement of other Anti-Smuggling Equipments .

DEMAND NO. 45 DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

The Government (United Front) had, in August, 1996, set up a Public Sector Disinvestment Commission with the mandate of advising the Government on the need, extent and mode of disinvestments the Government should undertake in Central Public Sector Enterprises referred to it by the Government. The term of this Commission expired in November, 1999. The government (NDA) thereafter in July, 2001 reconstituted the Disinvestment Commission with the same mandate as that of the previous Commission. The extended term of the Commission was up to 31st October, 2004.

2. The National Common Minimum Programme (NCMP) of the present Government (UPA) adopted in June, 2004 envisages inter-alia strengthening of Public Sector Enterprises and that profit making PSEs will generally not be privatized. While presenting the Budget for 2005-06, the Government announced in the Parliament in July, 2004, that the Government would set up a Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE). In accordance with the present policy of the Government the terms of Disinvestment Commission was not extended and it was wound up from 1st November, 2004. The Government has since set up the BRPSE under the Department of Public Enterprises on 6th December, 2004.